36.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बाह परियोजना का संशोधित प्रस्ताव 3/84 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुआ था । इससे 19863 हेक्टेयर क्षेत्र की सालाना सिंचाई करने की परिकल्पना है । केन्द्रीय जल आयोग में जांच के बाद परियोजना को 29.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 4/88 में इस शर्त पर परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरणीय/वन स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं । सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना न किये जाने के कारण परियोजना को 8/91 में राज्य को लौटा दिया गया ।

संशोधित सागर परियोजना का जल विज्ञान अध्याय मई, 1984 में केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त हुआ था । जल विज्ञान अध्याय पर केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास और पुर्नस्थापना स्वीकृतियां, यथास्थिति, प्राप्त करती है ।

Ground water level in Gujarat

6184. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) wheher it is a fact that ground water level is going down day-by-day in Gujarat State for irrigation purpose;

(b) if so, the details thereof;

(c) wheher Government have formulated any plan to get water from other sources for irrigation purposes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. However fall in the level of ground water has been observed in certain parts of the State.

(b) As per the observations made by the Central Ground Water Board in January, 1994 fall of 2 to 4 metres and more than 4 metres in the level of ground water in relation to similar observations made in January, 1993 was observed in certain parts of the Districts of Kuchch, Jamnagar, Rajkot, Junagarh, Amreli, Bhavnagar and Banaskhantha.

(c) and (d) Yes, Sir. In order to tap the surface water resources, also for irrigation purposes the State Government is having 9 major, 25 medium and 12 extension/renovation/modernisation ongoing projects.

Over extraction of ground water

6185. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a report prepared by a group of researchers of Delhi University which has been published in the State of the World, 1994 (the annual report of the World Watch Institute, Washington) regarding the alarming situation developing in Ludhiana District as a result of over extraction of ground water i.e. 30 per cent higher than replenishment;

(b) the strategies being worked out by Government to prevent any further calamity in water resource management and the details thereof in response to each main finding of the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The Government has not come across the report prepared by a group of researchers of Delhi University published in the State of World

1994. Efforts are being made to obtain it. However, according to the assessment made by the Central Ground Water Board, an apex organisation of the country in the field of ground water, the level of ground water development in Ludhiana is 123.16 per cent.

(b) The Central Ground Water Board has prepared guidelines for formulation of Artificial Recharge Scheme by the State Government and the drafts manual containing guidelines for formulation of Artificial Recharge Scheme has been circulated by the Board to the State Government.

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनायें

6186. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनाओं की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं में से कितनी पूरी हो चुकी हैं और उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनका कार्य अभी चल रहा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को बाण सागर परियोजनाओं को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या सरकार बाण सागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर विचार करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुन्गन) : (क) सिंचाई क्षेत्र में किसी भी परियोजना को "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परिकलित व्यापक अवधारणा/मानदण्डों के अनुसार, बाण सागर परियोजना भी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है ।

सरकारी और निजी स्रोतों के द्वारा कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

6187. **श्री राघवजी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार देश में सरकारी और निजी संसाधनों के द्वारा सिंचित कृषि योग्य भूमि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में जिनमें सिंचित भूमि की प्रतिशतता काफी कम है प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुन्गन) : (क) सरकार और निजी स्रोतों से निबल सिंचित क्षेत्र सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं । कृषि मंत्रालय के अद्यतन भूमि प्रयोग सांख्यिकी 1990–91 (अनन्तिम) में दिए अनुसार राज्यवार कुल कृष्य क्षेत्र, कुल निबल सिंचित क्षेत्र तथा कुल कृष्य क्षेत्र में